www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 322 | जौनपुर सोमवार, 13 जुलाई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ की चेतावनी के बाद वापस भागा पाकिस्तानी घुसपैठिया

जम्मू, (एजेंसी)। जम्मू–कश्मीर के कठुआ जिले में रविवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली। यहां भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को सीमा सुरक्षा बल के मुस्तैद जवानों ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाकर वापस खदेड़ दिया। अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि की है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, रविवार शाम को बीएसएफ के जवानों ने हीरानगर सेक्टर के बोबिया इलाके में सीमा पर एक संदिग्ध गतिविधि देखी। वहां एक पाकिस्तानी घुसपैठिया भारतीय सीमा की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा था। जवानों ने तुरंत हरकत में आते हुए उसे वहीं रुकने की चेतावनी दी। बीएसएफ के जवानों की चेतावनी को अनसुना करते हुए वह घुसपैठिया लगातार सीमा पर लगी बाड़ की ओर बढ़ता रहा। इसके बाद, सतर्क जवानों ने स्थिति को भांपते हुए चेतावनी के तौर पर कुछ गोलियां चलाईं। फायरिंग की आवाज सुनते ही घुसपैठिया घबरा गया और तुरंत वापस पाकिस्तानी सीमा की तरफ भाग गया।

कैग ने उजागर किया 3,541 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च

मुबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र सरकार की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक श्लाडकी बहिनश योजना के क्रियान्वयन में गंभीर वित्तीय कमियां सामने आई हैं। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने इस योजना के तहत करीब 3,541.16 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च और वित्तीय प्रबंधन में बड़ी कमियों को उजागर किया है। शुक्रवार को राज्य विधानमंडल में पेश की गई वर्ष 2024–25 की कैग राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस भारी–भरकम अतिरिक्त खर्च को लेकर कोई विशिष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया है। रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, महिला एवं बाल विकास विभाग को इस योजना के लिए कुल 29,693.09 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था, जिसके मुकाबले विभाग ने कुल 33,237.24 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। इस वजह से योजना में तय सीमा से 3,541.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ। इस योजना के लिए सरकार द्वारा कुल 29,693.09 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया था, जिसमें अनुपूरक प्रावधानों के माध्यम से प्राप्त 26,200 करोड़ रुपये और श्लेक लाड़की योजनाश से पुनर्वियोजित किए गए 3,490.75 करोड़ रुपये शामिल थे। इसके अलावा, कैग ने सरकारी धन को नियम विरुद्ध तरीके से जमा खातों में ट्रांसफर करने पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। ऑडिट जांच से यह खुलासा हुआ है कि जनवरी और मार्च 2025 के बीच सरकारी खजाने से निकाली गई 15,586 करोड़ रुपये की एक बड़ी राशि को आभासी वैयक्तिक जमा लेखा (वीपीडीए) में ट्रांसफर कर दिया गया था।

पीएम लक्सन ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए आधारित नई डील का किया ऐलान

ऑकलैंड, (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड समेत तीन देशों का छह दिवसीय दौरा खत्म कर चुके हैं। पीएम मोदी के दौरे के खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने जानकारी दी है कि न्यूजीलैंड और भारत एक नए समझौते पर सहमत हुए हैं जो हमारे मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर आधारित है। पीएम लक्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ष्न्यूजीलैंड और भारत एक नई डील पर सहमत हुए हैं जो हमारे मुक्त व्यापार समझौते पर आधारित है। न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, हमने अपने संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है, जिसमें 2030 तक हमारे देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने की योजना है। इसका मतलब है कि कीवी समुदाय में ज्यादा पैसा वापस आएगा, नौकरियां पैदा होंगी और घर पर सैलरी बढ़ेगी।ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। पीएम क्रिस्टोफर लक्सन उनसे गले मिले और हाथ हिलाकर गुडबाय कहा। छह दिवसीय आधिकारिक विदेश दौरे के आखिरी चरण में वे राजधानी ऑकलैंड पहुंचे थे। दौरा बेहद सफल रहा। 18 बड़े फैसले और 10 समझौतों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुरानी दोस्ती, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, लोगों के बीच गहरे संबंधों और हिंद–प्रशांत में साझा हितों को देखते हुए, दोनों पीएम ने आपसी संबंधों को श्रणनीतिक साझेदारीश तक बढ़ाने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने अगले चार सालों में मिलकर काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क के तौर पर भारत–न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी रोडमैप टू 2030 का समर्थन किया। दोनों पक्षों ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के बीच नियमित दौरे और बैठक करने पर सहमति जताई, जिसमें क्षेत्रीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों के दौरान होने वाली बैठकें भी शामिल हैं।

अमित शाह ने जनता से की पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी की अपील

अहमदाबाद, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण में जन–भागीदारी बनाए रखने की अपील की है। केंद्र सरकार की कोशिशों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पिछले 7 सालों में 7 करोड़ पौधे लगाने का काम पूरा किया है। अमित शाह ने रविवार को गुजरात के अहमदाबाद में श्मिशन फाइव मिलियन ट्रीजश के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देशव्यापी कोशिशें विकास के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण पर फोकस को दर्शाती हैं। गृह मंत्री शाह ने कहा, ष्केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने शनिवार को ही सात सालों में सात करोड़ पौधे लगाने का काम पूरा किया।ष उन्होंने बताया कि दो दिन पहले दिल्ली रिज क्षेत्र में भी 43 लाख पौधे लगाए गए। गृह मंत्री शाह ने कहा कि इस अभियान के तहत चुने गए पौधे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल और देसी प्रजातियों के हैं, जो 100 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं।

उन्होंने कहा, ष्अगर आप आज इन्हें लगाते हैं, तो आपके पोते–पोतियां भी इनकी छांव में बैठेंगे। इनमें से किसी भी पेड़ की उम्र 100 साल से कम नहीं है। हमने जान–बूझकर ऐसे पेड़ चुने हैं जो एक सदी से अधिक समय तक जीवित रहते हैं।ष अमित शाह ने कहा कि बरगद और पीपल जैसी प्रजातियां न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड सोखती हैं, बल्कि पक्षियों को भोजन और आश्रय भी देती हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा, ष्बरगद या पीपल का पेड़ लगाएं, और वह अकेला पेड़ हजारों पक्षियों को आश्रय, भोजन और पानी देता है।

लखनऊ –कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन– सीएम योगी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और गडकरी ने फीता काटकर किया लोकार्पण

लखनऊ–कानपुर, (संवाददाता)। लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे के लोकार्पण समारोह के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सेना के हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पहुंच गए। हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद चारों नेताओं का जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। लोकार्पण से पहले सभी अतिथियों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्हें लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे की निर्माण प्रक्रिया, परियोजना की प्रमुख विशेषताओं और इससे होने वाले लाभों की जानकारी दी गई। इसके बाद सभी अतिथि मुख्य मंच पर पहुंचे। कुछ ही देर में 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। समारोह स्थल पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद हैं लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे के चालू होने से जिले के लोगों को भी सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। यह एक्सप्रेसवे दो हाईवे को जोड़ रहा है। इसी कारण जिलेवासी इस एक्सप्रेसवे के जरिए एक तरफ लालगंज रायबरेली पहुंच सकेंगे। वहीं, दूसरी ओर कानपुर–लखनऊ हाईवे पर भी आ जा सकेंगे। एनएचएआई के अफसरों के मुताबिक, इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते समय टोल चुकाने के लिए गाड़ी की रफ्तार कम नहीं करनी होगी और न ही कोई बैरियर होगा। टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले लगे हाई डेफिनेशन कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट और फास्टैग को रफ्तार में ही स्कैन कर लेंगे।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली पीएम-उदय योजना के पहले चरण के लिए केंद्र से मांगी 100 करोड़ की वित्तीय सहायता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली में संशोधित पीएम–उदय (प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियों के विकास एवं उत्थान योजना) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार से प्रथम चरण में 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर यह वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने रविवार को एक विज्ञप्ति करते हुए कहा कि 6 अप्रैल को अधिसूचित संशोधित विनियमों के तहत अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की प्रक्रिया को नया कानूनी आधार मिला है। इसके साथ ही श्जैसी स्थिति है, उसी आधार परश अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की व्यवस्था लागू होने से लाखों लोगों को संपत्ति अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया और अधिक सरल एवं प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को पीएम–उदय योजना के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि नई जिम्मेदारियों के तहत राजस्व विभाग को दिल्ली के सभी 13 जिलों में पीएम–उदय प्रकोष्ठ स्थापित करने होंगे, जिनका नेतृत्व एडीएम करेंगे। इसके अलावा दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों का भौतिक सत्यापन, आधुनिक तकनीक के माध्यम से डिजिटल मैपिंग तथा भू–अभिलेखों को अप–टू–डेट करने का व्यापक कार्य किया जाएगा। इन सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए वर्ष 2026–27 में प्रथम चरण के रूप में 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई गई है। मुख्यमंत्री ने पत्र में प्रस्तावित व्यय का विस्तृत विवरण भी दिया है। इसके अनुसार 65 करोड़ रुपये डीआरआईएस एचटीआई पहल के तहत आधुनिक भू–सर्वे एवं मैपिंग प्रणाली विकसित करने पर खर्च किए जाएंगे। इससे संपत्तियों के सत्यापन और भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण की पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सटीक और तकनीक आधारित बन सकेगी।

पश्चिम बंगाल दौरे पर शिवराज सिंह चौहान, कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा

कोलकाता, (एजेंसी)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 और 14 जुलाई को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। साथ ही जूट किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों की जानकारी लेंगे। 14 जुलाई को कोलकाता के नए सचिवालय भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्र के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और आईसीएआर के अधिकारी भी शामिल होंगे। इस दौरान पीएम–किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि धनधान्य योजना, विकसित भारत–जी राम जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास और पंचायतों को मिलने वाले फंड सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। शिवराज सिंह चौहान 13 जुलाई की शाम दिल्ली से कोलकाता पहुंचेंगे। उनके कार्यक्रम में राज्य नेतृत्व के साथ कृषि, किसानों के कल्याण, ग्रामीण सड़क, आवास और रोजगार जैसे विषयों पर चर्चा भी शामिल है। दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री बैरकपुर स्थित आईसीएआर–सीआरआईजैफ (केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान) पहुंचेंगे। यहां वह जूट किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से सीधे संवाद करेंगे। बैठक में जूट की खेती में रेटिंग, सिंचाई, रोग–कीट प्रबंधन, लागत, मूल्य और जूट वैल्यू चेन में किसानों की भागीदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वैज्ञानिक बेहतर जूट किस्मों, आधुनिक तकनीकों, जल संरक्षण और प्रोसेसिंग–मार्केटिंग से जुड़े उपायों की जानकारी देंगे। महिलाओं को जूट आधारित उत्पादों और वैल्यू एडिशन के जरिए स्वरोजगार और आय बढ़ाने के मॉडल भी बताए जाएंगे।

कतर के पूर्व अमीर खलीफा अल थानी के निधन पर भारत ने जताया शोक

मुबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र ने सोमवार को देश के अन्य राज्यों के साथ कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल–थानी के निधन पर एक दिन का राजकीय शोक मनाया। शेख हमद बिन खलीफा अल–थानी का रविवार को निधन हो गया था, जिसके बाद भारत सरकार ने सोमवार को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। महाराष्ट्र, केरल और नई दिल्ली से सामने आई तस्वीरों में कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल–थानी के निधन पर राष्ट्रपति भवन सहित विभिन्न सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ दिखाई दिया। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। वहीं, मुंबई तथा केरल के सरकारी भवनों पर भी तिरंगा आधा झुकाकर श्रद्धांजलि दी गई। केरल के लिए यह शोक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि राज्य का बड़ा प्रवासी समुदाय खाड़ी देशों से जुड़ा है और वहां के साथ उसके घनिष्ठ आर्थिक एवं जन–से–जन संबंध हैं। भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप केरल सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जिन सरकारी भवनों और संस्थानों पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, वहां इसे आधा झुकाया जाए। जिला कलेक्टरों को अपने–अपने अधिकार क्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालयों को राष्ट्रीय शोक की जानकारी देने तथा भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा, "भारत सरकार ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल–थानी के सम्मान में 13 जुलाई को एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इस दिन पूरे भारत में उन सभी सरकारी और अन्य भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, जहां नियमित रूप से तिरंगा फहराया जाता है। साथ ही, इस दिन कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।" केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जल्द ही कतर जा सकते हैं।

56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में स्वर्ण जीतने वाले भारतीय दल को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई

कोलंबिया, (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड (आईपीएचओ) 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय दल को बधाई दी है। उन्होंने कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत बेंडाले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी की उपलब्धि को देश के लिए गर्व का क्षण बताते हुए उनकी सफलता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय छात्रों की यह उपलब्धि देश की युवा शक्ति की असीमित क्षमता तथा विज्ञान एवं अनुसंधान के प्रति उनके समर्पण और जुनून का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ऐसे युवा देश के वैज्ञानिक भविष्य को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारतीय छात्रों ने अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड के विभिन्न संस्करणों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस उपलब्धि को देश के लिए प्रेरणादायक बताते हुए विजेता छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, "हमारे युवाओं का शानदार प्रदर्शन!" उन्होंने 56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत बेंडाले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी को हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सफलता युवा शक्ति की असीमित क्षमता और विज्ञान एवं अनुसंधान के प्रति उनके जुनून का प्रतीक है।

कभी शहर की शान रहा नरेंद्रालय प्रेक्षागृह आज जर्जर भवन और कबाड़ मे तब्दील

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।शहर के रिकाबगंज मे स्थित नरेंद्रालय प्रेक्षागृह आज अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है।कभी शहर की शान रहा यह प्रेक्षागृह संबंधित विभाग के अधिकारियों तथा कर्मियों की अनदेखी के चलते जर्जर अवस्था में पहुंच गया है।बताते चले कि 6 मार्च 1983 को उसे समय अयोध्या नगर निगम का नाम नगर पालिका फैजाबाद जाना जाता था उसके द्वारा निर्मित नरेंद्रालय प्रेक्षागृह का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्रीपति मिश्र ने किया था।इसका उद्घाटन उस समय विधायक रहे तथा पूर्व राज्य मंत्री निर्मल खत्री के अध्यक्षता में हुआ था।मालूम हो कि नरेंद्रालय प्रेक्षागृह की पहचान कभी सांस्कृतिक, सामाजिक और सरकारी आयोजनों के प्रमुख केंद्र के रूप में होती थी।यहां वर्षों तक यहाँ विवाह समारोह,स्कूलों, राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण सभाएं, सरकारी कार्यक्रम, सम्मान समारोह, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और जनजागरूकता अभियान आयोजित होते रहे।वही शहर के हजारों लोगों की यादें इस भवन से जुड़ी हैं,लेकिन आज यही प्रेक्षागृह अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है।भवन का अधिकांश हिस्सा जर्जर हो चुका है। परिसर में जगह–जगह कबाड़ पड़ा है,दीवारें उखड़ रही हैं,रंग–रोगन वर्षों से नहीं हुआ और रखरखाव के अभाव में पूरा परिसर वीरान नजर आता है।कभी जहां लोगों की भीड़ रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है।स्थानीय लोगों का कहना है कभी इसका बड़ा नाम था और इसमें लोगों के कई कार्यक्रमों का आयोजन भी होता था।यदि समय रहते इस प्रेक्षागृह का जीर्णोद्धार कराया जाए तो यह एक बार फिर शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रमुख केंद्र बन सकता है।लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस ऐतिहासिक धरोहर की जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन अभी तक नगर निगम, विकास प्राधिकरण अथवा संबंधित विभाग अब तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली।राम नगरी अयोध्या में जहां करोड़ों रुपये विकास कार्यों पर खर्च किए जा रहे हैं,वहीं शहर की वर्षों पुरानी इस महत्वपूर्ण धरोहर की अनदेखी कई सवाल खड़े कर रही है।यदि समय रहते संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह भवन पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो सकता है।शहर के बुद्धिजीवियों और सामाजिक संगठनों का मानना है कि इस भवन का पुनर्निर्माण अथवा व्यापक जीर्णोद्धार कराया जाए ताकि यहां फिर से सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी आयोजन, साहित्यिक गोष्ठियां और सामाजिक गतिविधियां शुरू हो सकें।इससे शहर को एक आधुनिक सभागार भी मिलेगा और वर्षों पुरानी विरासत भी सुरक्षित रहेगी।बल्कि उससे प्राप्त होने वाला राजस्व भी सरकारी खजाने में जमा होगा।साथ ही राजनैतिक के साथ साथ गैर–राजनीतिक,सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक कार्यक्रमों के आयोजन से नगर निगम और प्रशासन को नियमित आय प्राप्त हो सकती है।ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि करोड़ों रुपये की संभावित आय और जनहित से जुड़े इस महत्वपूर्ण भवन को आखिर कब तक उपेक्षा का शिकार कब तक बने रहने दिया जाएगा

संपादकीय

बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून कहां है

बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून कहां है? या ऐसे कानूनों का कोई मतलब नहीं होता, जिन पर अमल संभव बनाने के लिए जमीनी स्थितियों को बदलने की ठोस योजना पर काम ना हुआ हो? छिहत्तर साल पहले लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत गुलामी जैसी किसी प्रथा को निषिद्ध घोषित किया गया। मगर बंधुआ मजदूरी को कानूनन प्रतिबंधित करने में 26 साल और लगे। 1976 में बंधुआ मजदूरी पर रोक का कानून पारित हुआ। अब उसके बाद 50 साल और गुजर चुके हैं। लेकिन जमीनी हकीकत उत्तर प्रदेश के मुजफ्घ्फरनगर जिले का मांडी गांव है, जहां दोना बनाने वाली फैक्टरी से 12 बंधुआ मजदूर छुड़ाए गए हैं। वैसे मांडी गांव भी सिर्फ एक झांकी है। बंधुआ और बाल बंधुआ मजदूरों से काम लेने या कभी–कभार उन्हें छुड़ाने की खबरें अक्सर हमारे सामने आती रहती हैं। मांडी की घटना बहुचर्चित हुई, तो इसलिए कि वहां मजदूरों से बर्बरता की इंतहा कर दी गई। उनकी दुर्दशा की कहानियों ने लोगों को झकझोरा है। पुलिस और उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग की संयुक्त कार्रवाई में छुड़ाए गए इन श्रमिकों के बारे में सामने आया है कि उन्हें कैदियों की तरह रखा गया, मोबाइल छीन लिए गए, पहचान–पत्र जला दिए गए और बाहर निकलने की मनाही कर दी गई। मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक के मुताबिक कुछ मजदूरों की पसलियां टूट गईं, कई के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं और आरोप है कि अत्याचार के चलते कुछ लोगों की मौत भी हुई। यह बात पुलिस ने कही है कि फैक्टरी में मजदूरों से जानवरों जैसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। उन्हें लोहे की गर्म रॉड, बेल्ट और डंडों से बुरी तरह पीटा जाता था। ये मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों से वहां काम की तलाश में वहां आए थे। तो प्रश्न है कि संवैधानिक उद्घोषणा और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून कहां हैं? या ऐसे कानूनों का कोई मतलब नहीं होता, जिन पर अमल संभव बनाने के लिए जमीनी स्थितियों को बदलने की किसी ठोस योजना पर काम ना हुआ हो? विचारणीय मुद्दा है कि अलग– अलग राज्यों से पलायन कर बंधुआ बनने के लिए किसी दूसरी जगह पर मजदूर क्यों आते हैं? दरअसल, ऐसी हर कहानी आजीविका की बदहाल सूरत का सबूत है, जो अपने लोकतंत्र पर एक गंभीर प्रश्न–चिह्न भी है।

सतलुज विवाद पर रवनीत सिंह बिट्टू ने जो सवाल उठाये हैं दिलजीत दोसांझ उनका जवाब देंगे

नीरज कुमार

पंजाब की राजनीति में एक बार फिर इतिहास, सिनेमा और सियासत आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह राजनीतिक बहस में बदल गया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने दिलजीत दोसांझ और फिल्म के निर्देशक हनी त्रेहन पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि फिल्म के जरिए पंजाब के उग्रवाद के दौर की केवल एकतरफा तस्वीर पेश की जा रही है और समाज में पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि केंद्र सरकार का फिल्म को ओटीटी मंच से हटाने में कोई हाथ नहीं है। साथ ही उन्होंने पूरे विवाद को सुनियोजित प्रचार करार दिया। हम आपको बता दें कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब सतलुज ओटीटी पर रिलीज होने के महज दो दिन बाद ही वहां से हटा ली गई। इस कदम के बाद पंजाब के फिल्म जगत, सोशल मीडिया और पंजाब सरकार के कुछ हलकों में यह सवाल उठने लगे कि क्या राजनीतिक दबाव के चलते फिल्म हटाई गई। हालांकि रवनीत सिंह बिट्टू ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि सरकार का ऐसे मंचों पर कोई नियंत्रण नहीं है। उनका दावा है कि फिल्म के निर्माताओं ने स्वयं ही इसे हटाया क्योंकि उन्हें जितना आर्थिक लाभ चाहिए था, वह मिल चुका था। उन्होंने कहा कि जब स्वयं दिलजीत दोसांझ पहले ही यह कह चुके थे कि फिल्म केवल दो तीन दिन के लिए उपलब्धा रहेगी, तभी समझ जाना चाहिए था कि पूरे घटनाक्रम में कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को फिल्म हटानी ही होती तो उसे प्रसारित होने की अनुमति ही क्यों दी जाती। बिट्टू ने आरोप लगाया कि पहले फिल्म को प्रसारित कर माहौल बनाया गया और फिर उसे हटाकर सरकार पर प्रतिबंध लगाने का आरोप मढ़ दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने दिलजीत दोसांझ पर केवल इस विवाद तक हमला सीमित नहीं रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिलजीत केवल धन कमाने के लिए काम करते हैं और विदेश में बैठकर पंजाब के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें बहुरूपिया बताते हुए कहा कि वह लॉस एंजिलिस में रहकर पंजाब की भावनाओं से खेल रहे हैं। बिट्टू ने सवाल उठाया कि यदि दिलजीत को समाज और मानवाधिकारों की इतनी चिंता है तो उन्होंने मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा पर फिल्म क्यों नहीं बनाई? उन्होंने फिल्म चमकीला का भी जिक्र करते हुए कहा कि यदि दिलजीत अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान करते तो ऐसी फिल्म में काम नहीं करते। उन्होंने यह दावा भी किया कि विदेशों में अपने कार्यक्रमों के दौरान दिलजीत खालिस्तान के झंडे लेकर आने वालों को हटाने की बात करते हैं और फिर सवाल उठाया कि आखिर उनके पीछे कौन–सी ताकतें काम कर रही हैं? रवनीत सिंह बिट्टू ने स्पष्ट किया कि उन्हें पंजाब में उग्रवाद के दौर पर फिल्म बनने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका विरोध केवल एकतरफा कहानी दिखाने को लेकर है। उन्होंने कहा कि यदि उस दौर की कहानी दिखाई जा रही है तो उन पुलिस अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों और निर्दोष नागरिकों के बलिदान को भी सामने लाया जाना चाहिए जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपने प्राण गंवाए। उन्होंने दिलजीत दोसांझ और हनी त्रेहन को चुनौती देते हुए पूछा कि क्या वह उन पुलिस अधिकारियों और आम नागरिकों पर भी फिल्म बनाएंगे जिनकी 1984 के बाद के दौर में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। उन्होंने लालडू के पास एक सौ पच्चीस यात्रियों के नरसंहार और युवा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अविंदर सिंह की हत्या जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन परिवारों के दर्द को भी देश के सामने लाया जाना चाहिए। फिल्म में किए गए उस दावे पर भी केंद्रीय मंत्री ने सवाल उठाया जिसमें पच्चीस हजार अज्ञात शवों के गुप्त तरीके से निपटान की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि यदि यह दावा तथ्यात्मक है तो निर्माता उसके प्रमाण सार्वजनिक करें। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि पच्चीस हजार तो दूर, यदि पांच हजार मामलों का भी पूरा ब्यौरा मीडिया, संबंधित आयोग या न्यायालय के सामने रख दिया जाए तो वह अपनी बात वापस लेने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तथ्यों के बिना ऐसे गंभीर आरोप समाज में भ्रम और तनाव पैदा करते हैं। अपने परिवार के इतिहास का जिक्र करते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि उनके दादा और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह ने आतंकवाद के कठिन दौर में राज्य में शांति बहाल करने के लिए संघर्ष किया था और इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि उस समय पंजाब में भय का ऐसा माहौल था कि सामान्य सामाजिक जीवन भी प्रभावित हो गया था। विवाह समारोहों से लेकर महिलाओं के पहनावे तक पर आतंक का साया था। उन्होंने उस दौर की तुलना कट्टर शासन से करते हुए कहा कि आज की शांति बहुत कठिन संघर्ष के बाद मिली है और इसे केवल फिल्म की कमाई या राजनीतिक लाभ के लिए दांव पर नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म में घटनाक्रम की समयरेखा को लेकर गंभीर सवाल हैं। उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह खालरा के लापता होने की घटना उनके दादा की हत्या के बाद हुई थी और उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में उस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी किसकी थी, इस पर भी सवाल उठना चाहिए। उन्होंने अकाली दल पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि गांवों और गुरुद्वारों में फिल्म का प्रदर्शन कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जसवंत सिंह खालरा की पत्नी ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर भी गंभीर आरोप लगाए थे, जिनकी चर्चा आज नहीं की जाती। साथ ही रवनीत सिंह बिट्टू ने सोशल मीडिया पर भी अपनी बात विस्तार से रखते हुए कहा कि इतिहास की केवल एक तरफा नहीं, बल्कि पूरी सच्चाई को जानना जरूरी है। उन्होंने लिखा कि पंजाब ने अपने निर्दोष लोगों के बलिदान के साथ जो असहनीय पीड़ा झेली है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उनका कहना था कि हर पीड़ित को याद किया जाना चाहिए और हर पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्थायी और वास्तविक शांति केवल सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। बिट्टू के अनुसार यदि इतिहास के केवल एक हिस्से को दिखाया जाएगा और दूसरे पक्ष के दर्द तथा बलिदान को नजरअंदाज किया जाएगा तो समाज में संतुलित विमर्श कभी स्थापित नहीं हो सकेगा। उनका कहना है कि पंजाब के उग्रवाद के दौर की कहानी में केवल कुछ घटनाओं या कुछ पात्रों को केंद्र में रखना न्यायसंगत नहीं है, बल्कि उन हजारों निर्दोष परिवारों, पुलिसकर्मियों, सुरक्षाबलों और आम नागरिकों के दर्द को भी बराबर महत्व मिलना चाहिए जिन्होंने आतंकवाद की कीमत अपने जीवन से चुकाई। बहरहाल, फिलहाल सतलुज को लेकर छिड़ा विवाद केवल एक फिल्म तक सीमित नहीं रह गया है।

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति का व्यावहारिक रास्ता

श्रीपाद

वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता, ऊर्जा की बढ़ती मांग और जलवायु से जुड़ी गंभीर चुनौतियों के इस दौर में, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ऐसी ऊर्जा प्रणालियों का निर्माण करने की जरूरत है जो स्वच्छ व अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित, सस्ती एवं भरोसेमंद होने के साथ–साथ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विकास संबंधी जरूरतों तथा आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप भी हों। स्वच्छ ऊर्जा दरअसल ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से तेजी से अहम होती जा रही है। यह ईंधन बाजार में आने वाले उतार–चढ़ाव से पैदा होने वाले जोखिमों को कम कर सकती है, ऊर्जा को अपेक्षाकृत अधिक सुलभ बना सकती है, रोजगार सृजित कर सकती है, घरेलू उद्योगों को मजबूत कर सकती है और देश को अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ बना सकती है। फिर भी, स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के रास्ते एक जैसे नहीं हो सकते। इन रास्तों को राष्ट्रीय परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों और विकास की प्राथमिकताओं के हिसाब से निर्धारित किया जाना चाहिए। इसी बिंदु पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच आपसी सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच बेहतर सहयोग से स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ–साथ ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समावेशी विकास के साझा लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत का अपना अनुभव यह बताता है कि स्वच्छ ऊर्जा की शुरुआत लोगों से ही होनी चाहिए। पिछले दशक में, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत लगभग 28.6 मिलियन घरों को बिजली के कनेक्शन दिए गए। इससे सभी तक बिजली पहुंचाने का काम आगे बढ़ा और ग्रामीण व कम सुविधा वाले इलाकों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत महिलाओं को 105 मिलियन से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए। इससे खाना पकाने के साफ–सुथरे तरीकों को बढ़ावा मिला, घर में सेहत बेहतर हुई और कठिन श्रम का बोझ कम हुआ। ये पहल एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को रेखांकित करती हैंरू स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने को केवल स्थापित मेगावाट या जोड़ी गई क्षमता के आधार पर नहीं मापा जा सकता, बल्कि इससे पैदा हुए अवसरों, सुदृढ़ हुई आजीविका और बेहतर हुए जीवन स्तर के आधार पर भी मापा जाना चाहिए। लोगों को प्राथमिकता देने वाले इस दृष्टिकोण के साथ–साथ बड़े पैमाने पर काम और सहयोगी बुनियादी ढांचे की भी जरूरत है। भारत की स्वच्छ ऊर्जा की कहानी में नवीकरणीय ऊर्जा अहम हो गई है। लेकिन इसकी सफलता इसे समर्थन प्रदान करने वाली प्रणालियों पर निर्भर करती है। सौर और पवन ऊर्जा को तेजी से अपनाया जा सकता है, लेकिन इनकी पूरी क्षमता का लाभ तभी मिल पाएगा जब पारेषण (ट्रांसमिशन), वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन), भंडारण (स्टोरेज) और ग्रिड प्रबंधन एकसाथ मिलकर काम करें। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में सहायता प्रदान करने वाली प्रणालियों को मजबूत करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। पारेषण संबंधी बुनियादी ढांचे (ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर) का निरंतर विस्तार हुआ है। इसके साथ–साथ ऊर्जा के भंडारण (एनर्जी स्टोरेज) और ग्रिड की सुदृढ़ता (ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी) के क्षेत्र में भी निवेश बढ़ा है। वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) संबंधी सुधारों और उन्नत ग्रिड तकनीक को अपनाने से एक ऐसी बेहतर एवं भरोसेमंद ऊर्जा प्रणाली बनाने में मदद मिली है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी को समन्वित करने में सक्षम है। भारत की गैर–जीवाश्म ईंधन पर आधारित क्षमता अब 288 गीगावॉट से अधिक हो गई है। बड़े पैमाने की परियोजनाओं के अलावा, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) प्रणालियां दृ जैसे कि रूफटॉप सोलर, सोलर पंप, मिनी–ग्रिड और माइक्रो–ग्रिड दृ ग्रामीण और कम सुविधा वाले इलाकों में स्वच्छ ऊर्जा को और अधिक सुलभ बना रही हैं। ये प्रणालियां सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज, स्कूलों, हेल्थकेयर सेंटरों तथा स्थानीय व्यवसायों को मदद पहुंचाने के साथ–साथ ग्रामीण आजीविका और स्थानीय आर्थिक सुदृढ़ता को भी बढ़ावा दे रही हैं। भारत की श्पीएम सूर्य घररू मुफ्त बिजली योजनाश्च बड़े पैमाने पर इस दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस योजना से अब तक लगभग 4 मिलियन परिवारों को लाभ हुआ है, जिससे उपभोक्ता अपेक्षाकृत अधिक विकेन्द्रीकृत एवं भागीदारी वाली ऊर्जा प्रणाली में योगदान देने वाले बन पाए हैं। हालांकि, स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में वित्त पोषण सबसे अहम तत्वों में से एक बना रहेगा। कई विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने तथा बैंक से ऋण पाने योग्य परियोजनाओं में बदलने हेतु सस्ती और दीर्घकालिक पूंजी की जरूरत होती है। आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा, वितरण संबंधी बुनियादी ढांचा, ग्रिड के आधुनिकीकरण, भंडारण प्रणाली और कम ऊर्जा खर्च करने वाली तकनीकों में निवेश बेहद जरूरी होगा।

विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना होगा

खुशाल

विद्यार्थी केवल दूसरों को सलाह देने तक सीमित न रहें, बल्कि स्वयं अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करें। यदि वे सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखें, अनावश्यक प्लास्टिक का उपयोग न करें, पानी और बिजली की बचत करें, पौधों की नियमित देखभाल करें तथा प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, तो उनका आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। इन दिनों विद्यालयों में वन–महोत्सव के अंतर्गत पौधारोपण के विशेष अभियान चल रहे हैं। विद्यार्थी उत्साह के साथ पौधे लगा रहे हैं, उनकी देखभाल का संकल्प ले रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम केवल औपचारिक गतिविधियां नहीं हैं, बल्कि बच्चों और युवाओं में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के तेजी से होते दोहन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या विशेषज्ञों का विषय नहीं रह जाता। यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बन चुका है। इस जिम्मेदारी को निभाने में विद्यार्थियों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि वे केवल भविष्य के नागरिक ही नहीं, बल्कि समाज को नई दिशा देने की क्षमता भी रखते हैं।इसके लिए पहली आवश्यकता है, विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना। विद्यालय इस दिशा में सबसे प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। श्इको–क्लब,श प्रकृति भ्रमण, पोस्टर प्रतियोगिताएं, भाषण, वाद–विवाद, निबंध लेखन और विज्ञान प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को केवल जानकारी ही नहीं देते, बल्कि उन्हें पर्यावरण संरक्षण से भावनात्मक रूप से भी जोड़ते हैं। जब कोई विद्यार्थी किसी पौधे को अपने हाथों से लगाता है और उसकी देखभाल करता है, तब उसके भीतर प्रकृति के प्रति अपनापन विकसित होता है। यही अपनापन आगे चलकर जिम्मेदारी में बदलता है।स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, उपजाऊ भूमि, घने वन और जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, किंतु इसका प्राकृतिक संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, नदियां दूषित हो रही हैं, भूजल तेजी से नीचे जा रहा है और अनियोजित विकास के कारण जंगलों का दायरा सिमटता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण कभी अत्यधिक वर्षा तो कभी लंबे सूखे जैसी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। इन समस्याओं का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है।आज का युवा रचनात्मक सोच और तकनीकी समझ से भरपूर है। विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में वे ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, जो पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। सौर–ऊर्जा से चलने वाले मॉडल, जैविक कचरे से खाद बनाने की तकनीक, वर्षा–जल संरक्षण के सरल उपाय, कम लागत वाले जल–शुद्धिकरण मॉडल और ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों पर विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे प्रयोग यह साबित करते हैं कि सही मार्गदर्शन मिलने पर वे समाज के सामने व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। कई विद्यार्थी डिजिटल माध्यमों और मोबाइल अनुप्रयोगों के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध करा रहे हैं। तकनीक का यह सकारात्मक उपयोग भविष्य के लिए नयी आशा जगाता है।भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में हिमालय से लेकर समुद्र तक, घने जंगलों से लेकर मरुस्थलों तक, प्रकृति के अनेक रूप दिखाई देते हैं। इन प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा तभी संभव है, जब समाज का प्रत्येक वर्ग अपनी भूमिका निभाए। विद्यार्थी अपने स्थानीय परिवेश के अनुसार भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वे जलस्रोतों की स्वच्छता, वृक्षों के संरक्षण और जैविक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने, वर्षा जल संचयन और घर के आसपास और छतों पर हरियाली बढ़ाने जैसे प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। इतिहास पर्यावरण संरक्षण को केवल एक श्दिवसश या श्अभियानश तक सीमित नहीं रखा जा सकता। श्विश्व पर्यावरण दिवस,श श्वन महोत्सवश या श्पृथ्वी दिवसश जैसे अवसर हमें प्रेरणा अवश्य देते हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है। पौधारोपण का महत्व तभी है, जब लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल भी की जाए। अनेक बार उत्साह में हजारों पौधे लगा दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए प्रत्येक छात्र को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह केवल पौधा लगाएगा ही नहीं, बल्कि उसके वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल भी करेगा। विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को अधिक व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है। यदि विद्यार्थियों को पुस्तकों के अध्ययन के साथ ही स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं पर श्परियोजना कार्यश दिए जाएं, तो वे विषय को अधिक गहराई से समझ सकेंगे। अनुभव से प्राप्त ज्ञान हमेशा अधिक स्थायी होता है। जब विद्यार्थी स्वयं किसी नदी, जंगल, तालाब या उद्यान का महत्व समझते हैं, तब उनके भीतर प्रकृति के प्रति सम्मान स्वतरू विकसित होता है। यही सम्मान उन्हें पर्यावरण संरक्षण का सच्चा सहभागी बनाता है।यह भी आवश्यक है कि विद्यार्थी केवल दूसरों को सलाह देने तक सीमित न रहें, बल्कि स्वयं अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करें। यदि वे सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखें, अनावश्यक प्लास्टिक का उपयोग न करें, पानी और बिजली की बचत करें, पौधों की नियमित देखभाल करें तथा प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, तो उनका आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। समाज में स्थायी परिवर्तन हमेशा अच्छे उदाहरणों से आता है, केवल उपदेशों से नहीं। जब बच्चे स्वयं जिम्मेदारी निभाते हैं, तो बड़े भी उनके प्रयासों का सम्मान करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि पर्यावरण संरक्षण को नैतिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया जाए। प्रकृति ने हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन दिए हैं।

ऑटो म्यूटेशन और ऑटो डायवर्सन से जमीन संबंधी सेवाओं में ऐतिहासिक बदलाव

सुशासन के नए डिजिटल युग में राजस्व प्रशासन अब फाइलों और लंबित प्रकरणों के पारंपरिक चक्रव्यूह से बाहर निकल चुका है। राज्य शासन के राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग ने तकनीक को माध्यम बनाकर जमीन से जुड़ी सेवाओं का पूरी तरह कायाकल्प कर दिया है। ऑटो म्यूटेशन (स्वतरू नामांतरण) और ऑटो डायवर्सन (स्वतरू व्यवर्तन) जैसी जन–हितैषी व्यवस्थाओं ने विभाग को तेज, पारदर्शी और मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त बनाया है। इससे आम नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर, लंबे इंतजार और मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना से स्थायी मुक्ति मिली है। पहले रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए अलग से आवेदन और भौतिक सत्यापन की थकाऊ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति से अब यह स्वतरू संपन्न हो रहा है। इसके साथ ही, भूमि उपयोग परिवर्तन (डायवर्सन) के लिए आवेदन, प्रीमियम निर्धारण और शुल्क गणना को भी आधुनिक तकनीक से त्रुटिहीन बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का यह डिजिटल गवर्नेंस मॉडल आज देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा है। आंकड़ों की जुबानीरू सफलता की एक नई गाथा राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रामाणिक आंकड़े इस ऐतिहासिक परिवर्तन की गवाही देते हैं। राज्य में अब तक कुल 1 लाख 40 हजार 607 पंजीकृत विलेखों में से रिकॉर्ड 1 लाख 40 हजार 536 मामलों का सफलतापूर्वक ऑटो म्यूटेशन किया जा चुका है। संपूर्ण प्रदेश में केवल 71 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं, जिससे विभाग ने 99.95 प्रतिशत की अभूतपूर्व सफलता दर हासिल की है। वहीं दूसरी ओर, ऑटो डायवर्सन व्यवस्था के तहत कुल 5 हजार 661 आवेदन दर्ज किए गए, जिनमें से 4 हजार 739 मामलों का त्वरित निराकरण किया गया। इस प्रकार 83.71 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण कर यह साबित कर दिया गया कि जटिल तकनीकी प्रक्रियाओं को भी डिजिटल माध्यम से सुगम और पारदर्शी बनाया जा सकता है। राजस्व सेवाएँ सीधे नागरिक के जीवन, संपत्ति और निवेश से जुड़ी होती हैंय अतरू इनमें गति आने से राज्य की आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिली है। ऑटो म्यूटेशन ने बदली नामांतरण की तस्वीर किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद भू–अभिलेखों में नाम दर्ज होना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। पुराने दौर में पटवारियों और तहसील कार्यालयों के चक्कर काटना, दस्तावेजों की जांच में महीनों गंवाना और अनिश्चितता का सामना करना आम बात थी, जिसने भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया। आज छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल चुकी है। 1 लाख 40 हजार 607 पंजीकृत विलेखों में से 1 लाख 40 हजार 536 मामलों का स्वतरू नामांतरण होना यह दर्शाता है कि अब नागरिक को अपने हक के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। इस व्यवस्था से समय और धन की भारी बचत हो रही है और रिकॉर्ड रीयल–टाइम अपडेट होने से जमीनी धोखाधड़ी पर लगाम लगी है। इस सफलता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा एक सख्त तकनीकी लॉक सिस्टम विकसित किया गया है। इसके तहत, यदि किसी संपत्ति का एक भी पुराना ऑटो म्यूटेशन लंबित है, तो संबंधित सब–रजिस्ट्रार कार्यालय में उस संपत्ति की अगली रजिस्ट्री तब तक नहीं हो पाएगी जब तक पिछला म्यूटेशन क्लियर न हो जाए। यह कदम निचले स्तर के प्रशासनिक अमले को जवाबदेह बनाता है। ऑटो डायवर्सन से भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया हुई तेज कृषि भूमि को आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग में बदलना (डायवर्सन) शहरीकरण, निवेश और रोजगार सृजन की रीढ़ है। पहले आवेदकों को शुल्क, आवश्यक दस्तावेजों और समय सीमा की स्पष्ट जानकारी नहीं होती थी। फरवरी से जून 2026 के बीच 5 हजार 661 आवेदनों में से 4 हजार 739 का त्वरित निस्तारण यह दिखाता है कि विभाग ने गाइडलाइन दरों के आधार पर प्रीमियम निर्धारण जैसी पेचीदा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर दिया है। वर्तमान में जो 922 लंबित मामले हैं, उनके पीछे अपूर्ण दस्तावेज, चालान राशि में तकनीकी अंतर या नगर तथा ग्राम निवेश के मास्टर प्लान से भिन्न प्रयोजन होना जैसे व्यावहारिक कारण हैं। इन चुनौतियों को सार्वजनिक करना विभाग की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। जिला–वार प्रदर्शन ने दिखाई नई प्रशासनिक संस्कृति ऑटो डायवर्सन के क्रियान्वयन में जिलों के बीच एक स्वस्थ और परिणाम–उन्मुख प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, जो यह प्रमाणित करती है कि सुधार जमीनी स्तर पर लागू हो चुके हैं। कोरिया जिला कुल 59 प्रकरणों में से सभी 59 का शत–प्रतिशत निराकरण कर 100 प्रतिशत सफलता दर के साथ पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहा।कोरबा जिला 98.46 प्रतिशत की सफलता दर के साथ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इसी तरह मुंगेली जिला 94.16 प्रतिशत मामलों का निपटारा कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।बालोद जिला 93.72 प्रतिशत निस्तारण दर के साथ शीर्ष जिलों में शामिल रहा।धमतरी जिला कुल 165 प्रकरणों में से 153 का वैधानिक निराकरण कर 92.73 प्रतिशत सफलता दर के साथ राज्य में पाँचवाँ (शीर्ष–5) स्थान प्राप्त किया। धमतरी का यह प्रदर्शन नियमित समीक्षा और जवाबदेह कार्यशैली का परिणाम है। तकनीकी सुधार और नए डिजिटल मॉड्यूल्स विभाग अपनी वर्तमान उपलब्धियों से आगे बढ़कर एक एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण में जुटा है। एनजीडीआरएस एपीआई इंटीग्रेशन इसके माध्यम से सरकारी गाइडलाइन दरें सीधे पोर्टल से प्राप्त हो रही हैं, जिससे प्रीमियम का निर्धारण मानवीय हस्तक्षेप के बिना पूरी तरह स्वचालित और पारदर्शी हो गया है। यदि पहले से डायवर्टेड भूमि का आंतरिक उपयोग बदलना हो (जैसे आवासीय से वाणिज्यिक), तो इस मॉड्यूल के तहत निस्तारण के लिए 15 दिवस की समय सीमा तय की गई है। मल्टीपल खसरा मॉड्यूल एक से अधिक खसरों वाली भूमि के लिए अब एक ही आवेदन में अनेक खसरों का चयन, स्वतरू शुल्क गणना और ई–चालान की सुविधा मिलेगी। इसके लिए समय सीमा जुलाई 2026 रखा गया है। रिकवरी मॉड्यूल पुराने लंबित मामलों के निपटारे के लिए पूर्व भुगतानों की प्रविष्टि, शेष प्रीमियम की गणना, भू–राजस्व उपकर की मांग और एक उच्च स्तरीय रिकवरी डैशबोर्ड की व्यवस्था की जाएगी।इसके लिए समय सीमा अगस्त 2026 निर्धारित किया गया है। सुशासन का नया मॉडल बनता छत्तीसगढ़ यह ऐतिहासिक बदलाव सिर्फ तकनीकी आंकड़ों का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के पौने तीन करोड़ नागरिकों के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने का माध्यम है। किसान, गृहस्वामी, व्यापारी और औद्योगिक निवेशक सभी को अब घर बैठे अपने मोबाइल पर पारदर्शी सेवाएँ मिल रही हैं। दिसंबर 2026 तक के लिए तय किए गए रोडमैप के अनुसार, राज्य के सभी क्षेत्रों की सैटेलाइटध्ड्रोन मैपिंग, टीएनसीपी से एनओसी लिंकिंग और मुख्य भू–अभिलेख पोर्टल का वृहद् अपग्रेडेशन किया जाना है। ये कदम छत्तीसगढ़ को डिजिटल राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय बेंचमार्क के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार कर रहे हैं। तकनीक, संवेदनशीलता और जवाबदेही के इस बेजोड़ संगम से छत्तीसगढ़ ने जन–केंद्रित शासन की एक नई मिसाल पेश की है।

रेडक्रॉस और राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय ने संयुक्त रूप से किया वृक्षारोपण

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव' 'शाहजहांपुर' सीएमओ कार्यालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, एवं इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, द्वारा प्रदेश सरकार की मंशानुसार तथा जिलाधिकारी एवं इंडियन रेडक्रॉस

सोसाइटी के अध्यक्ष के निर्देशन में 'एक पेड़ माँ के नाम' जनजागरूकता अभियान के अंतर्गत संयुक्त रूप से

जन सुनवाई में जिलाधिकारी ने सुनी 71 शिकायतें

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' सोमवार को कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी अनुनय झा ने आमजन की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई में कुल 71 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके त्वरित निस्तारण के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण

समयबद्व और गुणवत्तापूर्ण पूर्ण हो। जनसुनवाई में प्राप्त कुछ शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही समाधान किया। जनसुनवाई में नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार व अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारीध्कर्मचारी उपस्थित रहे।

आरक्षी से मुख्य आरक्षी पर हुई पदोन्नति

अयोध्या।पुलिस लाइन में आरक्षी पद पर तैनात आशीष कुमार पांडे की पदोन्नति मुख्य आरक्षी पद पर हुई है।सोमवार को इस मौके पर एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने अपने कार्यालय पर आयोजित समारोह में उनके वर्दी पर मुख्य आरक्षी का प्रतीक चिन्ह लगाया।इस मौके पर वहां पर उपस्थित उनके अलावा अन्य पुलिस अधिकारियों ने मुख्य आरक्षी आशीष कुमार पांडे को बधाई दिया।

जौनपुर में 4 नए एसडीएम की तैनाती, 3 उप जिलाधिकारियों का हुआ तबादला

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में उत्तर प्रदेश शासन ने सोमवार को जारी प्रशासनिक तबादला सूची में जौनपुर के प्रशासनिक ढांचे में अहम बदलाव किए हैं। शासन ने जौनपुर में चार नए उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) की तैनाती की है, जबकि यहां कार्यरत तीन एसडीएम का स्थानांतरण अन्य जनपदों में किया गया है। नए अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभिन्न तहसीलों के प्रभार का पुनर्वितरण किया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार जौनपुर में तैनात सुनील कुमार भारती का स्थानांतरण मऊ, संतवीर सिंह का रामपुर तथा कुणाल गौरव का कुशीनगर उप जिलाधिकारी के पद पर किया गया है। वहीं शासन ने अलीगढ़ से मो. अमान, बहराइच से अखिलेश कुमार सिंह, स्थानीय निकाय निदेशालय में सहायक निदेशक पद पर कार्यरत रश्मि सिंह तथा फतेहपुर से प्रदीप कुमार रमन को जौनपुर में उप जिलाधिकारी के पद पर तैनात किया है। इन तबादलों के बाद जौनपुर के प्रशासनिक अमले में नए अधिकारियों की आमद होगी। शासन के निर्देशानुसार यह तबादला नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया गया है और संबंधित अधिकारी शीघ्र ही अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

संत रविदास एक्सप्रेस का जौनपुर सिटी में ठहराव वाराणसी-छेहर्टा के बीच चलेगी, 17 जुलाई से होगा संचालन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में वाराणसी और पंजाब के छेहर्टा के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस, जिसे श्संत रविदास एक्सप्रेसश नाम दिया गया है, का जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित किया गया है।इस संबंध में स्टेशन अधीक्षक सिटी स्टेशन अनिल कुमार उपाध्याय के अनुसार, इस ट्रेन का संचालन 17 जुलाई से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ करेंगे। यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन दोनों दिशाओं में संचालित होगी। छेहर्टा से वाराणसी जाने वाली ट्रेन (14624) बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। वहीं, वाराणसी से छेहर्टा जाने वाली ट्रेन (14623) गुरुवार, शनिवार और सोमवार को संचालित की जाएगी। जौनपुर सिटी के अलावा, इस ट्रेन का ठहराव सुल्तानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर सिटी और अमृतसर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भी होगा। इस नई रेल सेवा से जौनपुर के यात्रियों को लखनऊ और पंजाब के लिए तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। आधुनिक स्लीपर कोचों से सुसज्जित यह ट्रेन व्यापार, रोजगार, शिक्षा और धार्मिक यात्रा करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगी।

विनीत खंड-2 में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का सफल आयोजन

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रेरणादायी आह्वान पर ष्एक पेड़ माँ के नामष् अभियान के अंतर्गत विनीत खंड–2, गोमती नगर, लखनऊ में विनीत खंड–2 जन कल्याण समिति द्वारा भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय पार्षद अरुण कुमार राय रहे। उन्होंने स्वयं पौधारोपण कर नागरिकों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प दिलाया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ष्एक पेड़ माँ के नामष् अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति संरक्षण, मातृत्व के सम्मान तथा भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का जनआंदोलन है। उन्होंने विनीत खंड–2 जन कल्याण समिति द्वारा क्षेत्र में सामाजिक एकता, जनसहभागिता एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए सभी नागरिकों से

इस अभियान को जन–जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारियों एवं क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों ने उत्साहपूर्वक पौधारोपण किया तथा हरित, स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक पौधा केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वायु, हरियाली एवं सुरक्षित पर्यावरण की अमूल्य धरोहर है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से समिति के अध्यक्ष सुभाष मणि तिवारी, सचिव अशोक कुमार अरोड़ा, उपाध्यक्ष आर. एस. नेगी, उपाध्यक्ष उमेश बहादुर सिंह, कोषाध्यक्ष सीए कृपा शंकर वर्मा, संगठन सचिव बांके श्याम त्रिपाठी, महिला प्रमुख चंदा सिंह, उप सचिव रमेश सिंह, उप सचिव राजन कपूर, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. हरस, तथा समिति के अन्य पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएँ, युवा एवं क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में विनीत खंड–2 जन कल्याण समिति की ओर से सभी उपस्थित अतिथियों एवं नागरिकों का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण का संकल्प दोहराते हुए पर्यावरण संरक्षण के इस जनआंदोलन को निरंतर आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया।

डॉ. राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, अल्लीपुर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का भव्य आयोजन

अल्लीपुर, हरदोई। पर्यावरण संरक्षण, गिरते भूजल स्तर और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा प्रकृति संवर्धन के संकल्प के साथ, डॉ. राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, अल्लीपुर, हरदोई के प्रांगण में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस महाभियान में महाविद्यालय के भारी संख्या में छात्र–छात्राओं, शिक्षकों और एन.एस.एस. स्वयंसेवकों ने पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग की वरिष्ठ प्राध्यापिका प्रो. गीतांजलि मिश्रा ने अपने संबोधन में उपस्थित छात्र–छात्राओं और स्वयंसेवकों को पर्यावरण और जैव विविधता के बीच के गहरे संबंधों से अवगत कराया। उन्होंने कहा, ष्वृक्ष केवल लकड़ी या छांव का स्रोत नहीं हैं, बल्कि ये संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का आधार हैं। आज पौधारोपण करना समय की सबसे बड़ी मांग है।ष् विशिष्ट अतिथि जंतु विज्ञान विभाग के शिक्षाविद् डॉ. आशीष कुमार ने पर्यावरणीय असंतुलन और जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों पर चर्चा करते हुए युवाओं को स्थानीय प्रजाति के अधिक से अधिक पौधे लगाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉ. रविंकर वर्मा ने छात्रों को शिक्षा के साथ–साथ एक जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। वहीं, प्राचार्य डॉ. एस.एस. त्रिवेदी ने महाविद्यालय की एनएसएस इकाई के प्रयासों की सराहना करते हुए परिसर को पूर्णतः श्ग्रीन कैंपसश बनाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम का सफल संचालन एवं वृक्षारोपण इस वृहद वृक्षारोपण अभियान की परिकल्पना एवं इसका कुशल संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना और वृक्षारोपण कार्यक्रम के समन्वयकों डॉ. शशिकांत पांडेय, डॉ. रश्मि द्विवेदी, आनंद विशारद, पारुल गुप्ता, अवंतिका अस्थाना और संजीव अस्थाना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इन सभी प्रभारियों के कुशल मार्गदर्शन में परिसर में नीम, पीपल, बरगद, अशोक, आंवला और अमरूद सहित सैकड़ों छायादार और औषधीय पौधे रोपे गए। इस पुनीत कार्य में महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों ने भी बढ़–चढ़कर अपना योगदान दिया और स्वयं पौधे लगाकर छात्रों का उत्साहवर्धन किया। छात्रों का उत्साह और पर्यावरण संरक्षण की शपथ इस अवसर पर उपस्थित भारी संख्या में एनएसएस स्वयंसेवकों और विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बनता था। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र–छात्राओं और कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई, जिसमें सभी ने रोपे गए पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया। अंत में समन्वयक समिति द्वारा अतिथियों और विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। यह कार्यक्रम युवाओं में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता जगाने में एक मील का पत्थर साबित हुआ।

एक पेड़ माँ के नाम अभियान लोगों को पौधों से भावनात्मक रूप से जोड़ने का माध्यम है : गिरीश चंद्र यादव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के वृक्षारोपण महायज्ञ–2026 के तहत सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर द्वारा श्एक पेड़ माँ के नामश अभियान के अंतर्गत रविवार को जिलेभर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य कार्यक्रम विकासखंड करंजाकला के ग्राम काफरपुर में हुआ, जबकि सभी तहसीलों और विकासखंडों में भी बड़े स्तर पर पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव और विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इससे पहले दोनों जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. तथा अन्य अधिकारियों ने श्एक पेड़ माँ के नामश अभियान के तहत विधिवत पूजन–अर्चन के बाद पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित उत्तर प्रदेश का संदेश दिया। इसके बाद अतिथियों ने कृषि विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उद्यान विभाग, वन विभाग समेत विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों का उद्घाटन किया और योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही एनसीसी स्वयंसेवकों एवं आमजन को पौधे वितरित कर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनके संरक्षण का आह्वान किया। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. ने बताया कि इस वर्ष जौनपुर में 60 लाख 73 हजार 400 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्य कार्यक्रम स्थल पर 1001 पौधों का रोपण किया गया। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण तभी सफल माना जाएगा, जब लगाए गए पौधों का नियमित संरक्षण, सिंचाई, फेंसिंग और जियो–टैगिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि श्एक पेड़ माँ के नामश अभियान लोगों को पौधों से भावनात्मक रूप से जोड़ने का माध्यम है। जिस तरह हर व्यक्ति अपनी मां का सम्मान और संरक्षण करता है, उसी भावना से लगाए गए पौधे की भी देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने पीपल, बरगद और फलदार पौधों के अधिकाधिक रोपण पर जोर देते हुए वन विभाग को पौधों की नियमित देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एमएलसी बृजेश सिंह श्प्रिंशुश ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर चल रहा यह अभियान जनआंदोलन का रूप ले रहा है। उन्होंने प्रत्येक परिवार से अपनी मां के नाम कम से कम एक पौधा लगाने और उसे वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखने का संकल्प लेने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) दिव्या ने सभी अतिथियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए पौधों की नियमित देखभाल, जियो–टैगिंग और संरक्षण का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुनील यादव क्षेत्राधिकारी नगर, परियोजना निदेशक, जिला सूचना अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, स्वयंसेवी संगठन और ग्रामीण मौजूद रहे।

लायंस क्लब जौनपुर गोमती का बृहद पौधारोपण अभियान, 200 फलदार पौधों के संरक्षण का लिया संकल्प

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से लायंस क्लब जौनपुर श्गोमतीश द्वारा सोमवार को शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर बृहद पौधारोपण अभियान चलाया गया। जिले के डॉ अख्तर हसन रिजवी शिया पीजी कॉलेज,मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज, श्यामा आईटीआई कॉलेज में वहाँ के टीचर्स व कर्मचारियों ने भी बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। अध्यक्ष सै. हसनैन कमर श्दीपूश के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान के अंतर्गत लगभग 200 उन्नत प्रजाति के फलदार पौधों का रोपण किया गया। इनमें आम, जामुन, अमरूद, सहजन, कटहल सहित अन्य फलदार वृक्ष शामिल रहे। कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि क्लब ने केवल पौधारोपण तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि प्रत्येक पौधे के संरक्षण, नियमित देखरेख एवं निगरानी का भी संकल्प लिया। क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि पौधारोपण तभी सार्थक होगा, जब लगाए गए पौधे सुरक्षित रहकर विशाल वृक्ष का रूप धारण करें। अभियान के संयोजक लायन अनुराग सिंह एवं संयोजिका

लायन नूपुर सिंह ने इस पुनीत कार्य में उल्लेखनीय योगदान देते हुए सभी 200 फलदार पौधे उपलब्ध कराए। उनके इस सहयोग की सभी उपस्थित सदस्यों ने मुक्तकंठ से सराहना करते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायी पहल बताया। इस अवसर पर अरविंद बैंकर, वीरेन्द्र सिंह, संतोष साहू, धीरज गुप्ता, अनिल साहू, गौरव श्रीवास्तव, मनीष गुप्ता, तौफीक तसनीम फातिमा, प्रज्ञा मिश्रा सहित क्लब के अनेक सदस्यों ने उत्साहपूर्वक श्रमदान कर पौधारोपण किया।शिया पीजी कॉलेज में कार्यवाहक प्राचार्य डॉ जाकिर हुसैन, डॉ ज्ञानेंदु चतुर्वेदी डॉ संजय सिंह , आदिनाथ मिश्रा डॉ शादाब हैदर डॉ इरफान हैदर ,फैजान रजा, हसन रजा ,सहित अन्य कर्मचारियों ने एक–एक पौधा वही मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज में डॉक्टर जीवन यादव व उनके टीचर स्टाफ के साथ–साथ छात्र ,छात्राओ ने भी बढ़–चढ़कर बहुत पौधारोपण किया। कार्यक्रम का संचालन क्लब के सचिव लायन नवीन मिश्रा ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ष्पौधारोपण केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति, समाज और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प ले, तो पर्यावरण संतुलन स्थापित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। अंत में सभी सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प दोहराया।

खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, संघर्ष और आत्मविश्वास का प्रतीक है - ज्ञान प्रकाश सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर के धर्मापुर ब्लॉक के गजना गांव निवासी युवा पहलवान सौरभ यादव ने थाईलैंड में आयोजित जूनियर एशियाई कुश्ती चौंपियनशिप (अंडर–20) में रजत पदक जीतकर जौनपुर जिले के साथ–साथ देश का नाम भी रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि समाजसेवी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञान प्रकाश सिंह ने सौरभ यादव और उनके कोच अशोक सोनकर का सम्मान किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा कि सौरभ यादव की सफलता जौनपुर के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि जब कबीरुद्दीनपुर स्थित ज्ञान कुश्ती केंद्र के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए मैट उपलब्ध कराया गया था, तब खिलाड़ियों से केवल एक संकल्प लिया गया था कि वे अपनी प्रतिभा, मेहनत और अनुशासन के दम पर जौनपुर का नाम राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन करेंगे। सौरभ यादव ने अपनी शानदार उपलब्धि से उस

संकल्प को साकार कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, संघर्ष और आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। सौरभ की सफलता यह साबित करती है कि ग्रामीण प्रतिभाओं को यदि सही मार्गदर्शन और संसाधन मिलें, तो वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकती हैं। ज्ञान प्रकाश सिंह ने विश्वास जताया कि सौरभ यादव भविष्य में भी देश के लिए स्वर्णिम उपलब्धियां हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी यह सफलता जौनपुर के युवाओं के लिए प्रेरणा है और इससे जिले में कुश्ती सहित अन्य खेलों के प्रति नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। समारोह में मौजूद लोगों ने सौरभ यादव और उनके कोच को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

पीयू में एक पेड़ माँ के नाम के तहत हुआ वृहद पौधरोपण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार एवं कुलपति प्रो. वंदना सिंह के मार्गदर्शन में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, में ष्एक पेड़ माँ के नामष् अभियान के अंतर्गत रविवार को तीन चरणों में वृहद पौधरोपण महायज्ञ का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न स्थलों पर हुए इस अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्र–छात्राओं ने उत्साहपूर्वक पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रथम चरण में विश्वविद्यालय स्थित श्री विश्वेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण एवं आवासीय परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित वरिष्ठ आईएएस अधिकारी (नोडल अधिकारी) एवं प्रमुख सचिव मत्स्य श्रीमती धनलक्ष्मी के., जिलाधिकारी सैमुअल एन. पॉल, प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) श्रीमती दिव्या, फॉरेस्ट रेंजर श्रीमती शालिनी चौरसिया तथा कुलसचिव डॉ. विनोद

कुमार सिंह ने पौधरोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने अधिकाधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संदेश दिया। द्वितीय चरण में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तत्वावधान में विश्वविद्यालय के अमृत सरोवर परिसर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. शशिकांत यादव, छात्र कल्याण अधिष्ठाता, कार्यक्रम अधिकारी, स्वयंसेवकों, शिक्षक एवं कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता करते हुए पौधरोपण किया तथा पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया। तृतीय चरण में विश्वविद्यालय के मियावाकी वन में वृहद वृक्षारोपण महायज्ञ संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रो. राज कुमार ने कहा कि पौधरोपण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित एवं स्वच्छ पर्यावरण देने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर प्रो. मनोज मिश्र, प्रो. अविनाश, प्रो. प्रदीप कुमार, प्रो. गिरिधिर मिश्र, प्रो. रजनीश भास्कर, डॉ. अन्नू त्यागी सहित विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया पर मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी से नाराज कांग्रेस ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में सोशल मीडिया पर कथित धार्मिक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एडीएम परमानन्द झा को ज्ञापन सौंपकर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह और शहर कांग्रेस अध्यक्ष आरिफ खान के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी धर्म या धार्मिक महापुरुष के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करती है और ऐसे मामलों में प्रशासन को निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि पूनम सिंह नाम की एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता द्वारा पैगम्बर मुहम्मद साहब के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म या उसके आराध्य के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में शांति और सौहार्द बना रहे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि सभी धर्म समान रूप से सम्मान के पात्र हैं और किसी भी धर्मगुरु या धार्मिक प्रतीक के खिलाफ अभद्र टिप्पणी सामाजिक तनाव का कारण बन

सकती है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान डॉ. परमेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष राकेश सिंह श्डब्बूश, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संजय माली, सभासद शहनवाज मंजूर, अबुजर शेख, जिला सचिव इरशाद खान, मुहम्मद ताहिर सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बीएसए लाल चंद्र ने किया वृक्षारोपण

वृक्षारोपण कार्यक्रम तहत रविवार को बेसिक शिक्षा विभाग मे 14000 पौधे लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ।इस मौके पर बीएस लालचन्द्र ने कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया।इस मौके पर उन्होंने बताया कि सभी विकाखण्ड के संसाधन केन्द्रो एवं विद्यालयों में खण्ड शिक्षा अधिकारियों,अध्यापकों एवं बच्चों द्वारा लगाने और पौधों की देखरेख करने का निर्देश दिया गया है। कार्यक्रम में बीएसए लालचंद्र के अलावा कार्यालय के सभी कर्मचारी मौजूद रहे।

डीआईजी,एसएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों व कर्मियों ने किया वृक्षारोपण

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन परिसर में रविवार को डीआईजी सोमेन वर्मा,एसएसपी डा0 गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन परिसर मे वृक्षारोपण किया।इस मौके पर उनके अलावा एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी,एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी सहित अन्य पुलिस अधिकारियो कर्मियों ने वृक्षारोपण किया।वही इस मौके पर सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने थाना परिसरों में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर उनके संरक्षण एवं नियमित देखभाल का संकल्प लिया।

फरियादियों को त्वरित न्याय व क्षेत्र को अपराध मुक्त रखना प्रमुख प्राथमिकता - प्रतीक कुमार

अयोध्या।फरियादियों को त्वरित न्याय दिलाना तथा क्षेत्र को अपराध मुक्त रखना नवागत सीओ सदर प्रतीक कुमार की प्रमुख प्राथमिकता है।यह बातें उन्होंने कार्यभार ग्रहण करते समय बताई।उन्होंने क्षेत्र के जनता से अपील किया कि अगर उनके सर्किल मे संबंधित थानों व चौकी पर थानायक्ष व चौकी प्रभारी द्वारा समस्याओं को नहीं सुना जाता है तो वे वेहिचक अपनी समस्या को उनसे कह सकते है या फिर उनके सीयूजी नंबर पर बता सकते हैं। बताते चले कि वाराणसी जनपद से आये सीओ सदर प्रतीक कुमार अपनी कार्यशैली, जनसुनवाई और प्रभावी पुलिसिंग से अलग पहचान बनाई है।वाराणसी मे भी महत्वपूर्ण दायित्वों के निर्वहन में भी उनकी भूमिका सराहनीय रही है।पुलिस महकमे में उनकी पहचान ऐसे पुलिस अधिकारियों में की जाती है जो फरियादियों की समस्याओ का तुरंत निस्तारण करने व अपराध पर अंकुश लगाने मे की जाती हैं।उन्होंने कहा कि क्षेत्र को अपराध मुक्त करना उनकी प्रमुख प्राथमिकता है।कहा कि आने वाले सावन मेला सहित प्रमुख पर्वो को शांति पूर्वक ढंग से संपन्न कराना है। उन्होंने अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वह अपराध छोड़ेंगे या फिर उनके रहने तक क्षेत्र छोड़ें।कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हुए पाया गया तो पुलिस उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगी।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विश्व हिन्दू महासंघ ने किया वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर चलाए जा रहे श्एक पेड मां के नामश अभियान के तहत विश्व हिन्दू महासंघ, जौनपुर की ओर से रीड्स नॉलेज नेशन स्कूल परिसर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन के जिलाध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव बच्चा ने किया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में महामंत्री नवनीत श्रीवास्तव, संगठन मंत्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव श्शेखरश, महासचिव नीरज श्रीवास्तव,जिला मीडिया प्रभारी दीपक श्रीवास्तव, संयोजक सत्य प्रकाश श्रीवास्तव राजू, जिला उपाध्यक्ष उमाशंकर सेठ, सुरेश शर्मा सहित महिला प्रकोष्ठ की जिला संगठन मंत्री कल्पना श्रीवास्तव, जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष ज्योति श्रीवास्तव, कार्यकारिणी सदस्य वैष्णवी पांडे, आकृति श्रीवास्तव, अनुराधा श्रीवास्तव,आराधना बिंद, पिंकी सरोज, प्रेमा देवी, देवी एवं शकुंतला श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में संगठन की ओर से महामंत्री ने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा गया कि सभी के सहयोग, समर्पण और सक्रिय सहभागिता से यह वृक्षारोपण अभियान सफल एवं प्रेरणादायक बना। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए भविष्य में भी ऐसे जनजागरूकता कार्यक्रम निरंतर चलाने का संकल्प लिया गया।

फोरलेन समेत 758 करोड़ के विकास कार्यो की सौगात देंगे सीएम

गोरखपुर, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को एक फोरलेन सड़क समेत करीब 758 करोड़ अधिक की 24 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वह भटहट–बासंस्थान फोरलेन सड़क समेत 697 करोड़ 49 हजार रुपये की लागत वाली पांच सड़कों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही सड़क निर्माण एवं पर्यटन विकास से जुड़े, 60 करोड़ 63 लाख 96 हजार रुपये की लागत वाले 19 विकास कार्यो का शिलान्यास करेंगे। लोकार्पण और शिलान्यास का समारोह शनिवार दोपहर बाद बांसस्थान में होगा जहां मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी जिन सड़कों का लोकार्पण करेंगे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भटहट–बांसस्थान फोरलेन मार्ग है। 11.6 किमी लंबे इस मार्ग के फोरलेन में चौड़ीकृत हो जाने से न केवल एक बड़ी आबादी के लिए आवागमन सुगमता बढ़ी है बल्कि इसका फायदा आयुष विश्वविद्यालय जाने वालों को भी मिल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि फोरलेन कनेक्टिविटी हो जाने से प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय में आयुष पद्धतियों से इलाज कराने का क्रेज और बढ़ेगा। शिलान्यास की परियोजनाएं सड़क और पर्यटन विकास पर केंद्रित हैं। आयुष विवि का करेंगे निरीक्षण रू सीएम शनिवार को महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय का भी निरीक्षण और समीक्षा बैठक करेंगे। उनके द्वारा आयुष विश्वविद्यालय में पुरुष व महिला छात्रावास का लोकार्पण भी संभावित है। पुरुष छात्रावास का नामकरण ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की स्मृति में किया गया है जबकि महिला छात्रावास का नाम राप्ती रखा गया है। पौधारोपण महायज्ञ में सम्मिलित होंगे सीएम रू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर में प्रदेशव्यापी पौधरोपण महायज्ञ में सम्मिलित होंगे।

आरपीएफ व जीआरपी कर्मियों द्वारा कैंट रेलवे स्टेशन व आसपास चलाया जा रहा लगातार चेकिंग अभियान

अयोध्या। प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ कैंट रेलवे स्टेशन हरीश कुमार शाही व जीआरपी प्रभारी निरीक्षक अनिल प्रकाश सिंह के नेतृत्व में आरपीएफ उप निरीक्षक रचना यादव व जीआरपी के अन्य सुरक्षा कर्मियों द्वारा कैंट रेलवे स्टेशन परिसर कथा आसपास के इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया गया।इस मौके पर आरपीएफ तथा जीआरपी के पुलिसकर्मियों ने सक्रिय निगरानी में पिछले दिनों कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।इस मौके आरपीएफ उप निरीक्षक रचना यादव तथा जीआरपी के उप निरीक्षक व सुरक्षा कर्मियों द्वारा स्टेशन परिसर,सभी प्लेटफार्मों एवं ट्रेनों में यात्रियों को अनावश्यक चेन पुलिंग से होने वाले नुकसान,सामान चोरी से बचाव,जहरखुरानी गिरोहों की गतिविधियों तथा ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने के खतरों के प्रति जागरूक करते हुए दिखाई दिये।बताते चले कि आगामी श्रावण मास और रामनगरी में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ को देखते हुये यह अभियान सुरक्षा की दृष्टि से चलाया जा रहा है।इस मौके पर सुरक्षा कर्मी यात्रियों को यह भी समझा रहे है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, लावारिस वस्तु अथवा आपात स्थिति की सूचना तत्काल रेलवे हेल्पलाइन एवं आरपीएफ को दें।इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक कैंट रेलवे स्टेशन हरीश कुमार शाही तथा प्रभारी निरीक्षक जीआरपी कैंट रेलवे स्टेशन अनिल प्रकाश सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि रेल यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टि से जागरूक किया जा रहा है,वही स्टेशन परिसर के सभी प्लेटफॉर्मो,प्रतीक्षालय, रेलवे सर्कुलेटिंग एरिया,आरक्षण केंद्रों तथा ट्रेनों में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए भी यह अभियान चलाया जा रहा है।उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार चलेगा।

हर हर महादेव के जयकारों के साथ दर्जनों शिवभक्त अमरनाथ यात्रा पर हुए रवाना

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। सोमवार को थाना क्षेत्र हैदरगंज की ग्राम पंचायत हैदरगंज से बोल बम कांवरिया संघ के बैनर तले दर्जनों शिव भक्तों का जत्था बाबा बर्फानी अमरनाथ धाम दर्शन के लिए रवाना हुआ।शिवभक्तों को बाजार के गणमान्य नागरिकों और संघ के पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक विदा किया।इस दौरान भव्य समारोह में यात्रा पर जाने वाले सभी शिवभक्तों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया और उनकी यात्रा मंगलमय होने की कामना की गई। यात्रियों को ग्राम प्रधान राकेश गुप्ता, बोल बम कांवरिया संघ के अध्यक्ष एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिंस कसौधन, उपाध्यक्ष संजय कसौधन श्पानश्सहित राकेश अग्रहरी, जयप्रकाश अग्रहरी गुड्डू, उमंग कसौधन, पिंटू अग्रहरी, संजय अग्रहरी, रोहित जायसवाल, गोलू मोदनवाल, सतीश आदि ने अंगवस्त्र भेंट कर व मीठा खिलाकर विदा किया। यात्रा का नेतृत्व सचिन जायसवाल, मनदीप कसौधन, साहिल अग्रहरि,मिंकु गुप्ता, अंबेश मोदनवाल और हेमंत अग्रहरि कर रहे हैं।

सीवर लाइन पाइप बिछाने का कार्य अधूरा होने के चलते सड़कों पर दिखाई दे रहे गड्ढे

अयोध्या।शहर के अमानीगंज कालोनी के अलावा शहर के सभी कालोनियों, मुहल्लों, मुख्य मार्गों पर सीवर लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है।देखा जाये तो पिछले कई माह से शहर के वजीरगंज, हैदरगंज, फतेहगंज ओवर ब्रिज से देवकाली तिराहा, शक्तिनगर कालोनी,अश्विनी पुरम कालोनी, रीडगंज तिराहा,गुरु नानक पुरा,बछड़ा सुल्तानपुर, साहबगंज, के अलावा कई प्रमुख मार्गों व मोहल्लों, कालोनियों व प्रमुख मार्गो पर यह गंभीर समस्या बनी है।इन जगहों पर मुहल्लों व गलियों मे पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रहे है।जहाँ पर बड़े–बड़े गड्ढे देखे जा सकते हैं।यहां पर रह रहे स्थानीय लोगों व राहगीरों का मानना है की आने वाले बारिश के दिनों में ये गड्ढे काफी कष्टकारी साबित होंगे।परंतु इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित कार्यदाई संस्था व विभाग ध्यान नहीं दे रहे है।देखा जाये तो शहर के कई मुहल्लों,कालोनियों, मार्गो पर सीवर पाइप लाइन बिछाने का कार्य जल निगम के अलावा विभिन्न संस्थाओं द्वारा कराई जा रही है।जहां–जहां पर सीवर लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है वहां पर या तो कार्य अधूरा है या फिर उन जगहों पर बड़े–बड़े गड्ढे देखे जा सकते हैं।वही गड्ढे पाटने के नाम पर कुछ मिट्टी आदि संबंधित विभाग या कार्यदाई संस्था द्वारा डाल दी जा रही है।जो हल्की सी बारिश मे और मुसीबत बन रही है।जबकि अभी पूरी बारिश बाकी ही है।इधर से गुजरने वाले राहगीरों तथा स्थानीय लोगों को इस मिट्टी के चलते परेशानियों का सामना करना पड रहा है।स्थानीय लोगों ने बताया कि पाइप लाइन बिछाने के बाद संबंधित विभाग के कर्मचारियों ने इस मार्ग को वैसे ही छोड़ दिया जिसके चलते बड़े–बड़े गड्ढे हो गए।वही इधर बारिश होने के चलते इस गड्ढे में स्थानीय लोग व राहगीर चोटिल हो रहे है।परंतु इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित विभाग व कार्यदाई संस्था चुप्पी साधे है।

आरपीएफ कर्मियों द्वारा कैंट रेलवे स्टेशन पर जागरुता अभियान चलाकर रेल यात्रियों को किया जागरूक

अयोध्या। प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ कैंट रेलवे स्टेशन हरीश कुमार शाही के नेतृत्व में तथा उप निरीक्षक रचना यादव की सक्रिय निगरानी में पिछले दिनों से कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।इस मौके आरपीएफ उप निरीक्षक रचना यादव अपनी टीम के साथ स्टेशन परिसर,सभी प्लेटफार्मों एवं ट्रेनों में यात्रियों को अनावश्यक चेन पुलिंग से होने वाले नुकसान,सामान चोरी से बचाव,जहरखुरानी गिरोहों की गतिविधियों तथा ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने के खतरों के प्रति जागरूक करते हुए दिखाई दी।बताते चले कि आगामी श्रावण मास और रामनगरी में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ को देखते हुये यह अभियान सुरक्षा की दृष्टि से चलाया जा रहा है।इस मौके पर सुरक्षा कर्मी यात्रियों को यह भी समझा रहे है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, लावारिस वस्तु अथवा आपात स्थिति की सूचना तत्काल रेलवे हेल्पलाइन एवं आरपीएफ को दें। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक कैंट रेलवे स्टेशन हरीश कुमार शाही तथा उप निरीक्षक रचना यादव ने संयुक्त रूप से बताया कि रेल यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टि से जागरूक किया जा रहा है,वही स्टेशन परिसर के सभी प्लेटफॉर्मों,प्रतीक्षालय, रेलवे सर्कुलेटिंग एरिया,आरक्षण केंद्रों तथा ट्रेनों में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए भी यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार चलेगा।

एसडीएम मिल्कीपुर समेत आठ एसडीएम का हुआ स्थानांतरण

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।शासन ने पीसीएस संवर्ग के आठ अधिकारियों का स्थानांतरण गैर जिले कर दिया है।स्थानांतरित एसडीएम में बीकापुर की उप जिलाधिकारी श्रेया को श्रावस्ती व मिल्कीपुर के उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार को सीतापुर में उपजिलाधिकारी के पद पर भेजा गया है। डिप्टी कलेक्टर प्रवीण यादव को प्रतापगढ़, अभिषेक कुमार सिंह को मुरादाबाद, अरविंद कुमार तृतीय को शामली, रामप्रसाद त्रिपाठी को मथुरा, अशोक कुमार सैनी को मैनपुरी,नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त अशोक कुमार गुप्त का सोनभद्र स्थानांतरण हुआ है।स्थानांतरित अधिकारियों के स्थान पर शासन ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओएसडी वंदना पांडेय को उप जिलाधिकारी अयोध्या,ज्वाला प्रसाद को उप जिलाधिकारी कानपुर से सहायक नगर आयुक्त,नगर निगम अयोध्या,मोहित यादव लखनऊ से अयोध्या,राखी वर्मा को सीतापुर से अयोध्या,आनंद कुमार तिवारी को बाराबंकी से अयोध्या, संजीव कुमार यादव को मिर्जापुर से अयोध्या,बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झांसी के विशेष कार्याधिकारी लालकृष्ण एवं विनोद कुमार गुप्त को कुशीनगर से अयोध्या में उपजिलाधिकारी के पद पर भेजा गया है।

शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक अवैध रूप से संचालित हो रहे सैकड़ो कोचिंग तथा लाइब्रेरी

अयोध्या।शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कुकुरमुत्ते की तरह लाइब्रेरी कोचिंग संस्थान अवैध रूप से संचालित हैं।देखा जाए तो अवैध रूप से संचालित लाइब्रेरी तथा कोचिंग संस्थान ना तो अग्नि शमन विभाग के मानक पर खड़े उतर रहे हैं,और ना ही शिक्षा विभाग पर।ठीक इसके विपरीत इन अवैध कोचिंग संस्थान तथा लाइब्रेरी के संचार को द्वारा भोले भाले तथा गरीब तपके के छात्रों तथा उनके अभिभावकों से शिक्षा के नाम पर लाखों रुपए की वसूली कर रहे हैं।परंतु यहां पर अध्यनरत छात्र–छात्राओं की सुरक्षा के नाम पर इन संस्थानों पर ना तो अग्निशमन के यंत्र उपलब्ध हैं और ना ही अग्निशमन मानक के अनुसार निर्माण ही है।जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के मुताबिक पंजीकृत लाइब्रेरी तथा कोचिंग संस्थान महज तीन दर्जन तक ही हैं।जबकि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक सैकड़ो की संख्या में अवैध रूप से लाइब्रेरी तथा कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं।बीच–बीच में जब कभी अग्निकांड या फिर अन्य कोई प्राकृतिक आपदा कही इन कोचिंग संस्थानों तथा लाइब्रेरी पर होती है तब खानापूर्ति के लिए अयोध्या जनपद में भी कोचिंग संस्थान लाइब्रेरी स्कूल कॉलेज जो कि अवैध रूप से संचालित हैं उनके ऊपर शिक्षा विभाग के अधिकारी एक–दो दिन कार्यवाही करते हैं उसके बाद फिर मामला ठंडा बस्ती में चला जाता है।इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पवन कुमार तिवारी ने बताया शीघ्र ही जिले में अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों लाइब्रेरी स्कूल कॉलेज पर कार्यवाही की जाएगी।

कैंट रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था के चलते रेल यात्री परेशान

अयोध्या।अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर इस समय अव्यवस्था का बोलबाला है।जिसके चलते रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।इस समय सभी प्लेटफार्मो पर बारिश के चलते पानी भरा रहता है। वहीं प्लेटफार्म नंबर एक से दो तीन पर जाने के लिए सबवे में हल्की बारिश के चलते पानी भरा रहता है।वही प्लेटफार्म नंबर 1 से 2 तथा 3 पर जाने के लिए स्वाचलित सीढी भी बंद रहती है।सबवे में पानी भरे रहने तथा स्वचालित सीढ़ी बंद होने के चलते इन प्लेटफार्म को जाने के लिए पुल का सहारा लेना पड़ता है। बताते चले कि प्लेटफार्म नंबर दो तथा तीन से होकर गुजरने वाली ट्रेन से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को खासकर बुजुगों, दिव्यांगों, मरीजों को स्वचालित सीढ़ी ना व सबवे मे पानी भरे रहने के चलते पुल का सहारा लेना पड़ता है। जिसके चलते इन रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परंतु इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित रेल अधिकारियो तथा कर्मियों का ध्यान नहीं जा रहा है।

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला पुलिस कर्मियों ने महिलाओ को किया जागरूक

अयोध्या। शनिवार को मिशन शक्ति अभियान फेज–5 के तहत महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला के नेतृत्व मे महिला उप निरीक्षक सोनी, प्रिया, श्वेता ने महिला आरक्षी नीलम यादव महिला पीआरडी संतोषी व अन्य महिला पुलिस कर्मियों के साथ जिला महिला चिकित्सालय,जिला पुरुष चिकित्सालय,अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन सहित अन्य प्रमुख चौराहों तथा मार्गों पर मिशन शक्ति अभियान फेज – 5 के तहत महिलाओ व अन्य लोगो को जागरुक किया।इस मौके पर उन्होंने महिलाओ व बेटियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक व सुरक्षात्मक उपाय भी बताई।इन पुलिस कर्मियों ने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स की भी जानकारी दिया।उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं।

दर्शन नगर अंडरपास में जलभराव से स्थानीय लोग परेशान

अयोध्या। हल्की सी बारिश में दर्शन नगर अंडरपास में लगातार जलभराव की समस्या से स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।बारिश के बाद अंडरपास में कई फीट तक पानी जमा हो गया,जिससे दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। लोगों का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर बारिश में यही स्थिति बन जाती है। स्कूली बच्चों, कर्मचारियों और व्यापारियों को भी आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगो का कहना है कि बारिस के कारण अंडर पास में पानी भर जाता है आने व जाने में बहुत परेशानी होती है यही हम लोगों का मुख्य मार्ग है। यहां पर रहने वाले स्थानीय लोगों तथा राहगीरों का मानना है जब हल्की सी बारिश में जल भराव हो रहा है तो भारी बारिश में क्या हाल होगा।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।